भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2981

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2026 को दिया जाना है।

14 श्रावण, 1948 (शक)

महाराष्ट्र में सेमीकंडक्टर विनिर्माण समूहों को बढ़ावा देना

2981. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा देश में सेमीकंडक्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने एवं विस्तारित करने हेतु लगभग 7,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन का प्रस्ताव किया गया है तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सेमीकंडक्टर विनिर्माण, संयोजन, परीक्षण, पैकेजिंग, ओएसएटी/एटीएमपी तथा इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में सेमीकंडक्टर अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से संबंधित कोई परियोजना केंद्रीय सहायता हेतु अनुमोदित की गई है अथवा सरकार के विचाराधीन है तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) महाराष्ट्र, विशेष रूप से मुंबई तथा नवी मुंबई में सेमीकंडक्टर विनिर्माण समूहों को बढ़ावा देने तथा निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में सेमीकंडक्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परियोजनाओं के लिए अनुमोदित निवेश, स्वीकृत केंद्रीय प्रोत्साहनों, संभावित रोजगार सृजन तथा परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ङ):** माननीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, सरकार ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए संरचित और लक्षित नीतिगत पहलों को अपनाया। इन पहलों ने तैयार उत्पादों के विनिर्माण में मदद की, जिसके बाद सब-असेंबली, कंपोनेंट्स और अंततः मशीनरी और टूल्स का निर्माण हुआ। वित्तीय सहायता के अलावा, इन पहलों में एफडीआई सुधार, कर सुधार, श्रम सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) के उपाय जैसे गैर-वित्तीय समर्थन भी शामिल हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योजनाएं:

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

- बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना
- आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना
- इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) स्कीम
- इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना (एसपीईसीएस)
- इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस)
- मोबाइल फोन निर्माण योजना (एमपीएमएस)

संबंधित योजनाओं/पहलों के अंतर्गत दिए गए प्रोत्साहनों/सहायता का ब्यौरा www.meity.gov.in पर उपलब्ध है।

सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम:

सेमीकंडक्टर के महत्व को स्वीकार करते हुए, सरकार ने सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब्स सेमीकंडक्टर पैकेजिंग की स्थापना और भारतीय डिजाइन वाले चिप्स को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2022 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रोत्साहनों/सहायता का ब्यौरा www.ism.gov.in पर उपलब्ध है ।

सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत, सरकार ने लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपये की कुल निवेश प्रतिबद्धताओं के साथ 12 विनिर्माण परियोजनाओं को स्वीकृति दी है।

सेमीकंडक्टर डिजाइन:

किसी विशिष्ट कार्य या अनुप्रयोग को प्राप्त करने के लिए चिप की संरचना को परिभाषित करने में सेमीकंडक्टर डिज़ाइन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चिप डिज़ाइन एक अत्यंत गहन अनुसंधान एवं विकास, इंजीनियरिंग और बौद्धिक संपदा (आईपी) प्रक्रिया है, इसलिए सरकार सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना के माध्यम से स्टार्टअप और लघु एवं मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ अवसंरचनात्मक सहायता (जिसमें डिज़ाइन टूल तक निःशुल्क पहुंच शामिल है) प्रदान कर रही है। डीएलआई योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए चौबीस (24) सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं और इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन (ईडीए) टूल सपोर्ट के लिए 105 स्टार्टअप/एमएसएमई को स्वीकृति दी गई है। नीचे उल्लिखित कंपनियों को महाराष्ट्र राज्य में भारत सरकार से सहायता प्राप्त हो रही है:

#	नाम	स्थान	सहायता
1	मल्टी नैनो सेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	नागपुर	अनुदान और ईडीए उपकरण
2	आईमुंबई सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	मुंबई उपनगरीय	ईडीए उपकरण
3	पेंटारिस्क सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	पुणे	ईडीए उपकरण
4	मिलीमीटरचिप्स प्राइवेट लिमिटेड	नागपुर	ईडीए उपकरण
5	वासबीम प्राइवेट लिमिटेड	पुणे	ईडीए उपकरण

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी):

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, रक्षा और रसायन सहित विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण क्लस्टरों की स्थापना को प्रोत्साहित किया है। उनके दृष्टिकोण को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में क्रियान्वित किया गया है।

इस योजना के तहत, सरकार ने महाराष्ट्र के रंजनगांव में एक ईएमसी स्थापित किया है जो 297.11 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है।

इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस):

सरकार ने आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र को और गहरा करने और देश में सुदृढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स घटक इकोसिस्टम विकसित करने के लिए ईसीएमएस लॉन्च किया। इसका उद्देश्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी), निष्क्रिय घटकों, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल घटकों, उप-असेंबली, कैमरा मॉड्यूल, ऑप्टिकल ट्रांसीवर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत सामान जैसे प्रमुख घटकों में निवेश को आकर्षित करना है।

अब तक, महाराष्ट्र में ईसीएमएस योजना के तहत 14 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है जो पुणे, सतारा, अहमदनगर, नासिक, ठाणे, पालघर और औरंगाबाद में स्थित हैं।

सेमीकॉन 2.0:

इसके अलावा, पहले चरण के सफल कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,27,500 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 15.07.2026 को सेमीकॉन 2.0 को स्वीकृति दी है।

सेमीकॉन 2.0 संपूर्ण सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है और देश में एक सुदृढ़ और लचीले सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास में और तेजी लाएगा। कार्यक्रम छह रणनीतिक स्तंभों पर केंद्रित है: डिजाइन; मशीनें और सामग्री; अधिक फैब्स स्थापित करना; एटीएमपी/ओएसएटी उद्योग को सुदृढ़ करना; अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी); और डिजाइन और विनिर्माण के लिए प्रतिभा विकास।

*****